



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 7, 2001/कार्तिक 16, 1923

No. 299]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 7, 2001/KARTIKA 16, 1923

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2001

सं. 48 (आर ई-2001)/1997-2002

फा. सं. 01/94/180/544/ए एम 02/पी सी-4.—का. आ. सं. 283(अ) दिनांक 31-03-1997 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में यथा अधिसूचित निर्यात और आयात नीति के पैराग्राफ 4.11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा, वास्तविक निर्यात हेतु अग्रिम लाइसेंसों के संबंध में निर्यात दायित्व की अवधि में बढ़ाने हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्धारित करते हैं :—

- 1-4-97 को या उसके बाद जारी वास्तविक निर्यात हेतु अग्रिम लाइसेंसों के संबंध में, जहां निर्यात दायित्व को पूरा करने हेतु 30 महीनों की निर्धारित समयावधि अभी समाप्त नहीं हुई है, और जहां लाइसेंस धारक निर्धारित समयावधि के भीतर अपने निर्यात दायित्व को पूरा करने में असफल रही है, वह बैंक गारंटी प्रस्तुत करके सार्वजनिक सूचना की तारीख से निर्यात दायित्व अवधि को छह महीनों हेतु बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकता है। बैंक गारंटी में आयात की तारीख से लागू निर्यात दायित्व की अवधि तक अप्रयुक्त शुल्क मुक्त माल पर 24 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित सीमा शुल्क शामिल होगा। बढ़ाई गई अवधि में निर्यात दायित्व पूरा न करने की स्थिति में बैंक गारंटी को जब्त कर लिया जाएगा। बैंक गारंटी इस सार्वजनिक सूचना की तारीख से 12 महीनों की अवधि हेतु वैध होनी चाहिए।

स्तर धारक अथवा अन्यथा होते हुए विधिक वचनबद्धता हेतु पात्र आवेदकों समेत सभी को बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

2. अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन इस सार्वजनिक सूचना की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। लाइसेंस को मूलतः जारी करने वाला लाइसेंसिंग प्राधिकारी निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार प्रदान करने हेतु सक्षम होगा। उन मामलों में जहां बैंक गारंटी/बांड शुरू में ही सीमाशुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया हो, लाइसेंस धारक निर्यात अवधि में विस्तार मांगने हेतु प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी लेने वाले संबंधित सहायक सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को इस सार्वजनिक सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।
3. जिन मामलों में लाइसेंस धारक निर्यात दायित्व की अवधि छः महीने से कम बढ़ाने के लिए आवेदन करता है, तो इसकी मंजूरी लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा दी जायेगी और ऐसे मामलों में मांगी गई निर्यात दायित्व की अवधि के अतिरिक्त बैंक गारंटी छः महीनों

की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए। तथापि, ऐसे मामलों में, पहले से आवेदित अवधि के बाद निर्यात दायित्व की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।

4. तथापि, जिन लाइसेंसों के बारे में गलत बयानी/घोखेबाजी की जानकारी लाइसेंसिंग प्राधिकारी को मिलती है वहां निर्यात दायित्व की अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, जिन लाइसेंसों के संबंध में न्याय निर्णय आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं वहां निर्यात दायित्व की अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. जिन मामलों में लाइसेंस धारक ने इस सार्वजनिक सूचना के तहत दी गई सुविधा का लाभ नहीं उठाया है वहां इस सार्वजनिक सूचना जारी होने की तारीख से 60 दिन की समाप्ति पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
6. जिन मामलों में इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख, से पूर्व निर्यात दायित्व पूरा कर लिया गया है किन्तु यह निर्धारित निर्यात दायित्व की अवधि के बाहर है तो नियमितीकरण के प्रयोजन के लिए ऐसे निर्यात को निर्धारित निर्यात दायित्व के भीतर किया गया माना जाएगा बशर्ते आवेदक द्वारा 1 प्रतिशत या 5 प्रतिशत या दोनों संयोजन शुल्क का भुगतान किया गया हो। यदि 1 प्रतिशत या 5 प्रतिशत या दोनों संयोजन शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो इस मान्य बढ़ाई गई अवधि के भीतर किए गए निर्यात को 1 प्रतिशत या 5 प्रतिशत या दोनों संयोजन शुल्क का भुगतान करने पर नियमित किया जाएगा जो इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या निर्यात 18 महीनों की मूल निर्यात दायित्व की अवधि के छः महीनों के भीतर या 18 महीनों की मूल निर्यात दायित्व की अवधि की समाप्ति के 12 महीनों के भीतर किया गया है।
7. इस सार्वजनिक सूचना की तारीख के बाद किए गए निर्यातों को निर्यात दायित्व की पूर्ति के मद्दे माना जाएगा। सीमाशुल्क प्राधिकारी निर्यात खेप की अंतिम भिक्सा की स्वीकृति दे सकता है। तथापि, इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार निर्यात दायित्व में विस्तार की मंजूरी की प्रत्याशा में किए गए निर्यातों की पूरी जिम्मेवारी और जोखिम निर्यातक का होगा।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 7th November, 2001

No. 48(RE-01)/1997—2002

F. No. 01/94/180/544/AM02/PC-IV.—In exercise of powers conferred under paragraph 4.11 of the Export and Import Policy, 1997—2002, as notified in the Gazette of India Extraordinary, Part-II-Section 3—Sub-section (ii) vide S.O. No. 283(E) dated 31-3-97, the Director General of Foreign Trade hereby lays down the following guidelines for extension in export obligation period in respect of Advance Licences for physical exports.

1. In respect of Advance Licences for physical exports issued on or after 1.4.97, where the stipulated time period of 30 months for fulfilment of export obligation is over, and where the licence holder has failed to complete his export obligation within the stipulated time period, he can apply for extension of export obligation period for six months from the date of the public notice on submission of a Bank Guarantee, covering the Customs duty together with 24% simple interest on the unutilised exempt material from the date of import upto the period of export obligation sought for, which shall be forfeited in the event of non fulfilment of export obligation in the extended period. Bank Guarantee should be valid for a period of 12 months from the date of this public notice.

The Bank Guarantee shall be required to be submitted by all applicants including those eligible for LUT facility being status holders or otherwise.

2. The request for extension shall be filed with the concerned licensing authority within a period of 60 days from the date of the Public Notice. The licensing authority, which originally issued the licence, shall be competent to grant extension in export obligation period. In cases where BG/Bond has been initially executed with the Customs authority, the licence holder shall be required to furnish a certificate to this effect alongwith request for extension of EO within 60 days from the date of this public notice from the concerned Assistant Commissioner of Customs and Central Excise with whom the BG has been executed for seeking extension in EO period.

3. In cases where the licence holder applies for export obligation extension for a period of less than six months, the same shall be granted by the licensing authority and in such cases, the BG shall be required to be valid for a period of six months in addition to the period of export obligation sought for. However, in such cases, no further extension in EO period beyond the period already applied for shall be allowed.

4. However, no extension in export obligation shall be allowed in respect of the licences where misrepresentation/ fraud has come to the notice of the licensing authorities. Further, in respect of licences where adjudicating orders have already been passed, no extension in export obligation period shall be admissible.

5. In such cases where the licence holder has not availed the facility accorded under this Public Notice, adjudication proceeding shall be initiated on the expiry of 60 days from the date of this Public Notice.

6. In such cases where export obligation has been fulfilled prior to the date of this Public Notice but outside the prescribed export obligation period, such exports shall be deemed to have been made within the prescribed export obligation period for the purpose of regularisation of the case provided composition fee of either 1% or 5% or both, has been paid by the applicant. In case the composition fee either 1% or 5% or both has not been paid, the exports effected within this deemed extended period shall be regularised by payment of composition fee of either 1% or 5% or both depending upon whether the exports have been effected within six months from the expiry of original EO period of 18 months or 12 months or more from the expiry of original EO period of 18 months.

7. Exports made from the date of this public notice may be accepted towards discharge of export obligation. Customs may allow provisional clearance of export consignment. However, the exports made in anticipation of grant of extension in EO in terms of this public notice shall be entirely on the risk and responsibility of the exporter.

This issues in public interest

N. L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade

